



स्टॉक और प्रवाह, NPA को लेकर RBI के नए नियम

चर्चा में क्यों

वाणज्यिक बैंक कारोबार करते समय वभिन्न परसिपत्तियों में नविश करते हैं तथा व्यक्तियों और कम्पनियों को कर्ज़ देते हैं। जाहरि है, कुछ धनराशि एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कनिहीं वजहों से बैंकों की पूंजी फँस जाती है जिसका समय पर भुगतान संभव नहीं हो पाता है। भारतीय रज़िर्व बैंक की मानें तो सतिम्बर 2017 के अन्त तक देश में अनुसूचति वाणज्यिक बैंकों (ACB) का सकल एनपीए उनके कुल कर्ज़ का 10.2 प्रतिशत हो गया है।

NPA के संबंध में RBI के नये नियम

- बैंक अब किसी भी हालत में दबाव ग्रस्त कर्ज़ को एनपीए में डालने और वसूली के लिये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आइबीसी) के तहत कार्रवाई को टाल नहीं सकेंगे।
- केंद्रीय बैंक (भारतीय रज़िर्व बैंक) ने इस संबंध में नए दशानरिदेश जारी किये हैं।
- सरकार ने अपने इस कदम को डफिॉल्टरों के लिये चेतावनी करार दिया है।
- भारतीय रज़िर्व बैंक के नए ढाँचे का प्रस्ताव एनपीए मान्यता चक्र को तेज़ कर देगा, लेकिन डूबे हुए कर्ज़ के झमेले पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
- इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रज़िर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने प्रस्तावति ढाँचे को सरल बनाने के लिये प्रयास कर रहा है, जिसकी वज़ह से डूबे कर्ज़ फरि से सामने आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्गठित करते हुए सभी पुरानी योजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा।
- दो साल पहले आरबीआई की पहली संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) के बाद, सरकारी बैंकों ने तेज़ गरिावट की सूचना दी थी और वत्तीय वर्ष 2016 में इस प्रणाली में 2.7 लाख करोड़ रुपए के डूबे कर्ज़ जोड़े गए थे। इससे लगा था कि सबसे बुरी स्थिति खत्म हो गई है, लेकिन डूबे ऋण बढ़ोतरी में कमी अस्थायी साबति हुई है - चालू वत्ति वर्ष के पहले 9 महीनों में ही लगभग 1.7 लाख करोड़ एनपीए जोड़े गए थे।
- जाहरि है, वभिन्न पुनर्गठन योजनाओं की आड़ में बैंकों द्वारा कारपेट के तहत एनपीए का एक महत्त्वपूर्ण हसिसा तेज़ी से नकिल चुका था।
- भारतीय रज़िर्व बैंक ने CDR, SDR, S4A या 5/25 के तहत बैंकों की बही में अपक्षय को खत्म करने के लिये सही कदम उठाए हैं और नए ढाँचे के तहत उन्हें स्थापति कर दिया है।
- बैंकों को अब खाते पर प्रस्ताव प्रक्रिया शुरु करनी होगी जैसे ही यह संघ के भीतर किसी भी बैंक द्वारा SMA-0 (जसिमें भुगतान 1-30 दिनों से अतदिय हैं) खाते के रूप में वर्गीकृत होता है।
- रज़िर्व बैंक ने फँसे कर्ज़ों के समाधान के लिये वर्तमान में चल रहे आधा दर्जन नियम खत्म कर दिये हैं।
- अब किसी कर्ज़डफिॉल्ट के मामले में बैंकों को 180 दिन के भीतर उसका समाधान नकालना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उस खाते को दवालिया प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाना होगा।
- नए नियम के तहत 2,000 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा के लोन डफिॉल्ट के मामलों में बैंक अधिकारियों को 180 दिन के भीतर समाधान की योजना तैयार करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर उसे दवालिया प्रक्रिया में ले जाना होगा।
- नियम का पालन नहीं कर पाने वाले बैंकों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

करेंसी जमा अनुपात (CDR)

- लोगों द्वारा करेंसी में धारति मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारति मुद्रा के अनुपात को करेंसी जमा अनुपात (CDR) कहा जाता है। $CDR = CU/DD$ करेंसी जमा अनुपात से लोगों का तरलता अधमिन प्रतबिबिति होता है।
- यह शुद्ध रूप में व्यावहारिक प्राचल (Behavioral Parameter) है, जो अन्य बातों के अतरिकित व्यय संबंधी मौसम के स्वरूप पर नरिभर करता है। त्योहारों के मौसम में जब लोग अपनी जमा को इन मौसमों में होने वाले अतरिकित खर्चे के लिये नकदी में बदलते हैं तो करेंसी जमा अनुपात (CDR) बढ़ जाता है।

एस.डी.आर. (strategic debt restructuring)–

- इसके अन्तर्गत बैंक एन.पी.ए. से संबंधति कंपनियों को दिये गए ऋण को इक्वटी में बदलकर उसके प्रबंधन पर नयितरण कर सकते हैं, साथ ही बैंक 18 महीनों के अंदर इक्वटी को बेचकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं।

एस.डी.आर. (strategic debt restructuring)–

- इसके अन्तर्गत बैंक एन.पी.ए. से संबंधति कंपनियों को दिये गए ऋण को इक्वटी में बदलकर उसके प्रबंधन पर नयितरण कर सकती हैं, साथ ही बैंक

18 महीनों के अंदर इक्विटी को बेचकर अपने पैसे वापस ले सकती है ।

5/25 योजना–

- इसके तहत ऋण परशोधन की अवधि को 25 वर्षों तक बढ़ा दिया जाता है एवं प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के पश्चात ब्याज दरों को पुनः परिवर्तित करने का प्रावधान किया जाता है ।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-stock-and-flow-npa-rbi-new-rules>

